International Journal of Geography, Geology and Environment

P-ISSN: 2706-7483
E-ISSN: 2706-7491
IJGGE 2023; 5(2): 01-05
Received: 03-04-2023
Accepted: 04-05-2023

आर. एन. शर्मा
प्रोफेसर, भूगोल शास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत

रवि प्रकाश
शोधार्थी, भूगोल शास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
आर. एन. शर्मा
प्रोफेसर, भूगोल शास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत

राजस्थान राज्य में सामाजिक–आर्थिक विकास के स्तर में क्षेत्रीय विषमताएँ : एक भौगोलिक विश्लेषण

आर. एन. शर्मा, रवि प्रकाश

सारांश
किसी भी राष्ट्र के किसी प्रदेश या क्षेत्र में बढ़ती हुई समृद्धशीलता व कल्याणकारी कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए उस प्रदेश की सामाजिक–आर्थिक विकास का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। इस अध्ययन में राजस्थान राज्य में जिला स्तर पर सामाजिक–आर्थिक विकास में असमानताओं का आंकलन किया गया है। राज्य में सामाजिक–आर्थिक विकास स्तर निर्धारण के लिए 10 दस सामाजिक–आर्थिक विकास संकेतकों का इष्टतम संयोजन कर समग्र सूचकांक विधि (कम्पोजिट इंडेक्स मेथड) का प्रयोग कर सूचकांक मूल्य प्राप्त किये। निर्मित सामाजिक–आर्थिक विकास सूचकांक से ज्ञात होता है कि राजस्थान के विभिन्न जिलों के बीच सामाजिक–आर्थिक विकास स्तर में व्यापक असमानताएँ है। राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र एवं मध्य क्षेत्र, दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में अधिक विकसित है इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक–आर्थिक विकास भौतिक बांधाओं से नकारात्मक रूप से संबंधित है। राज्य के 23 जिले निम्न व अति निम्न विकसित श्रेणी में व 5 जिले मध्यम विकसित श्रेणी में मात्र 5 जिले उच्च व अति उच्च विकसित श्रेणी में शामिल है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 69.96 प्रतिशत भाग व कुल जनसंख्या का 60.81 प्रतिशत भाग निम्न व अति निम्न विकसित श्रेणी में आता है। राजस्थान के सामाजिक–आर्थिक विकास में क्षेत्रीय संतुलन और अन्तिम समाधान को सुरक्षित करने के लिए संसाधनों और क्षमताओं के उचित और कुशल उपयोग के आधार पर एक उपयुक्त विकास रणनीति व क्षेत्र विशिष्ट योजना दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

कूटशब्द : इष्टतम, समृद्धशीलता, संयोजन, समग्र सूचकांक विधि, विशिष्ट योजना

प्रस्तावना

विकास एक बहुआयामी संकल्पना है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व पर्यावरणीय आदि सूचकों के आधार पर किसी क्षेत्र के उन्नति के स्तर का निर्धारण किया जाता है। "किसी क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक चरों जिनमें आर्थिक प्रगति, जीवन स्तर में उत्थान, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक न्याय, नैतिकता, सामाजिक मूल्यों तथा सामाजिक सेवाओं इत्यादि के आधार पर विकास के स्तर का निर्धारण सामाजिक–आर्थिक विकास कहलाता है।" गुन्नार मिर्डाल (1968) ने अपने अग्रणी कार्य 'द एशियन ड्रामाः एन इंक्वायरी इन टू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस' में 'सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था का उर्ध्वगामी संचलन' के रूप में सामाजिक–आर्थिक विकास को परिभाषित किया है।

किसी क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक विकास में क्षेत्रीय विषमताएँ प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण हो सकती है या कुछ हिस्सों की उपेक्षा व कुछ को वरीयता देने के अर्थ में मानव निर्मित भी हो सकती है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान महान विविधताओं की भूमि है। इन भौतिक विभिन्नताओं ने राज्य में सामाजिक–आर्थिक विकास के स्तरों में क्षेत्रीय विषमताओं को जन्म दिया है। अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक विकास में क्षेत्रीय विषमताओं के गहन विश्लेषण के लिए तीन मूलभूत प्रश्न सामने आते हैं– असमान रूप से विकसित जिलों में इतना अंतर क्यों है? विकास के स्तर में अंतरजिला असमानता क्यों बढ़ रही है? विकास केवल कुछ ही क्षेत्रों तक क्यों सीमित है? इन सवालों का जवाब विभिन्न विकास संकेतकों के इष्टतम संयोजन से पिछड़ेपन के क्षेत्रों का निर्धारण व विश्लेषण से प्राप्त होंगें। प्राप्त परिणाम विकास की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन व भावी समय में क्षेत्र के विकास के लिए नियोजन रणनीति बनाने में उपयोगी होगें।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र राजस्थान राज्य भारत के उत्तर–पश्चिमी भाग में $23^{0}03'$ से $30^{0}12'$ उत्तरी अंक्षाशों के मध्य व $69^{0}30'$ से $78^{0}17'$ पूर्वी देशान्तरों के मध्य 342239 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41 प्रतिशत है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम में पाकिस्तान देश

(1070 कि.मी.) से लगती है। अर्न्तराज्य सीमा में उत्तर दिशा में पंजाब, हरियाणा, पूर्व दिशा में उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश व दक्षिण दिशा में गुजरात राज्य के साथ लगती है। अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 68548437 है जो देश की कुल जनसंख्या का 5.6 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र को प्रशासनिक दृष्टि से 33 जिलों व 7 संभागों में विभाजित किया गया है।

मानचित्र 1: अध्ययन क्षेत्र

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों को केन्द्र में रखा गया है–

1. सामाजिक–आर्थिक विकास के क्षेत्रीय वितरण का प्रारूप ज्ञात करना व उनका भौगोलिक आधार पर विश्लेषण करना।
2. अंतरजिला विकास की मौजूदा परिवर्तनशीलता की जाँ करना व साथ ही विकास में विविधता के लिए जिम्मेदार संकेतकों की पहचान करना।
3. विभिन्न जिलों में विकास संकेतकों के इष्टतम संयोजन के आधार पर सामाजिक–आर्थिक विकास के स्तर का अनुमान लगाना।
4. क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए उपयुक्त रणनीति सुझाना।
5. नियोजन रणनीति बनाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना।

परिकल्पना

शोध शीर्षक 'राजस्थान राज्य में सामाजिक–आर्थिक विकास में क्षेत्रीय विषमताएँ : एक भौगोलिक विश्लेषण' पर निम्नलिखित परिकल्पना है।

– अध्ययन क्षेत्र में विकास का स्तर भौतिक बाँधाओं से प्रभवित है।

आँकड़ा आधार व शोधविधि

प्रस्तुत अध्ययन विशेष रूप से द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। जिसमें भारत की जनगणना 2011, कृषि सांख्यिकीय 2015–16, आर्थिकी एवं सांख्यिकीय विभाग, कृषि विभाग व विभिन्न आधिकारिक स्त्रोतों के प्रतिवेदनों, प्रपत्रों व प्रकाशनों से प्राप्त आँकड़ों का प्रयोग किया गया है।

सामाजिक–आर्थिक विकास में क्षेत्रीय विषमता के निर्धारण के लिए 10 संकेतकों को विश्लेषण में शामिल किया गया है, जो इस प्रकार हैः–

1. 2001–2011 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत।
2. कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, 2011
3. साक्षरता दर प्रतिशत, 2011
4. महिला साक्षरता दर प्रतिशत, 2011
5. कुल जनसंख्या में स्नातक जनसंख्या प्रतिशत, 2011
6. शुद्ध बोया गया क्षेत्र प्रतिशत 2015–2016
7. शुद्ध बोया गया क्षेत्र में द्विफसली क्षेत्र प्रतिशत, 2015–16
8. कुल अनाज उत्पादन, लाख टन में, 2015–16
9. प्रति व्यक्ति आय, 2015–16

10. कुल जनसंख्या में श्रमिक जनसंख्या प्रतिशत, 2011

उपर्युक्त संकेतकों के आधार पर सूचनाएँ जिला स्तर पर एकत्रित कर विश्लेषित की गई है। सामाजिक आर्थिक विकास में स्थानिक विविधता के निर्धारण के लिए 'समग्र सूचकांक विधि' (ब्वउचवेपजम प्दकमग डमजीवक) का प्रयोग दो चरणों में कर विकास कटिबंधों का निर्माण किया गया।

(अ) चरण–प्रथमः प्रयुक्त संकेतकों का वर्गीकरण एवं संकेतकों का माध्य व मानक विचलन ज्ञात करना।

(ब) चरण–द्वितीयः मानक विचलन के आधार पर मूल्यों का स्कोर (मानक मूल्य) व समग्र सूचकांक मूल्य (ब्वउचवेपजम प्दकमग टंसनम) ज्ञात करना। उसके बाद ब्ण्प्टण से विकास कटिबंधों का निर्धारण।

अध्ययन को व्यापक एवं और अधिक विश्लेषणात्मक बनाने के लिए अनुभवजन्य एवं सांख्यिकीय दोनों पद्धतियों को अपनाया गया है।

सामाजिक–आर्थिक विकास स्तर का मूल्यांकन

सामाजिक–आर्थिक विकास स्तर मूल्यांकन के लिए चयनित 10 सूचकांकों का प्रत्येक का माध्य व मानक विचलन ज्ञात किया जाता है। सूचकांकों के मूल्यों को माध्य से घटाकर मानक विचलन से विभाजित करने पर प्रत्येक जिले के मानकीकृत मान प्राप्त होते हैं। प्रत्येक जिले के मानकीकृत मूल्यों के योग को चुने गए चर की संख्या से विभाजित कर समग्र सूचकांक तैयार किया जाता है।

तालिका 1: जिलेवार समग्र सूचकांक मूल्य

क्र.सं.	जिला	समग्र सूचकांक मूल्य	क्र.सं.	जिला	समग्र सूचकांका मूल्य
1.	अजमेर	0.22	18.	जैसलमेर	–0.56
2.	अलवर	0.71	19.	जालौर	–0.58
3.	बांसवाड़ा	–0.55	20.	झालावाड़	0.09
4.	बांरा	0.18	21.	झुंझुनू	0.20
5.	बाड़मेर	–0.44	22.	जोधपुर	0.08
6.	भरतपुर	0.24	23.	करौली	–0.24
7.	भीलवाड़ा	–0.05	24.	कोटा	1.44
8.	बीकानेर	0.29	25.	नागौर	–0.39
9.	बूंदी	0.15	26.	पाली	–0.56
10.	चित्तोड़गढ	0.11	27.	प्रतापगढ़	–0.30
11.	चुरू	–0.26	28.	राजसमंद	–0.40
12.	दौसा	0.11	29.	सवाईमाधोपुर	–0.14
13.	धौलपुर	–0.11	30.	सीकर	0.05
14.	डूंगरपुर	–0.66	31.	सिरोही	–0.69
15.	गंगानगर	0.85	32.	टोंक	–0.23
16.	हनुमानगढ़	0.68	33.	उदयपुर	–0.38
17.	जयपुर	1.13			

स्त्रोतः जनगणना प्रतिवेदन 2011, जनगणना विभाग राजस्थान, आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर, कृषि सांख्यिकी 2015–16, आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान में स्थानिक भिन्नता

समग्र सूचकांक (तालिका–1) के आधार पर राजस्थान के 33 जिलों को तालिका 2 में दर्शाए गए विकास स्तर की 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। समग्र सूचकांक का उच्च मूल्य विकास के उच्च स्तर को दर्शाता है एवं निम्न मूल्य निम्न स्तर को।

तालिका 2: राजस्थानः जिलेवार सामाजिक–आर्थिक विकास स्तर

क्र.सं.	विकास का स्तर	समग्र सूचकांक मूल्य (C.I.V.)	जिले	प्रतिशत क्षेत्र	प्रतिशत जनसंख्या
1.	अति उच्च विकसित	+1.44 से +1.04	कोटा, जयपुर	4.78	12.52
2.	उच्च विकसित	+1.04 से +0.58	अलवर, हनुमानगढ़, गंगानगर	8.49	10.82
3.	मध्यम विकसित	+0.58 से +0.16	अजमेर, बाँरा, भरतपुर, बीकानेर, झुंझुनू	16.47	15.84
4.	निम्न विकसित	+0.16 से –0.26	भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तोड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड, जोधपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक	28.77	31.98
5.	अति निम्न विकसित	–0.26 से –0.69	बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर।	41.49	28.83

अति उच्च विकसित

समग्र सूचकांक का मान +1.04 से अधिक मान वाले जिलों को विकास का अति उच्च स्तर का दर्जा दिया गया है। विकास के स्तर के मामले में कोटा +1.44 के समग्र सूचकांक मूल्य के साथ शीर्ष स्थान पर है व जयपुर +1.13 समग्र सूचकांक मूल्य के साथ इसमें शामिल है। दोनों जिलों में उच्च शिक्षा का स्तर, उच्च नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, प्रति व्यक्ति आय की उच्च मात्रा व कृषि विकास के सभी संकेतकों में उच्च स्तर सकारात्मक संबंध प्राप्त हुआ है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.78 प्रतिशत क्षेत्र इस क्षेत्र में शामिल है व राज्य की कुल जनसंख्या का 12.52 प्रतिशत भाग अति उच्च विकसित क्षेत्र में निवास करती है।

उच्च विकसित

+0.58 से +1.04 के मध्य समग्र सूचकांक मूल्य वाले जिलों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। इस श्रेणी में अलवर, हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों को शामिल किया गया है।

गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर जिलों में कृषि विकास का उच्च स्तर के साथ–साथ शैक्षणिक विकास व जनसांख्यिकीय विकास के औसत स्तर के कारण समग्र विकास की सुदृढ़ स्थिति है। अलवर जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने के कारण यहाँ की जनसांख्यिकीय संरचना पर नगरीय विशेषताओं का प्रभाव हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 8.49 प्रतिशत क्षेत्र उच्च विकसित है एवं राज्य की कुल जनसंख्या का 10.82 प्रतिशत भाग उच्च विकसित क्षेत्र में निवास करती है।

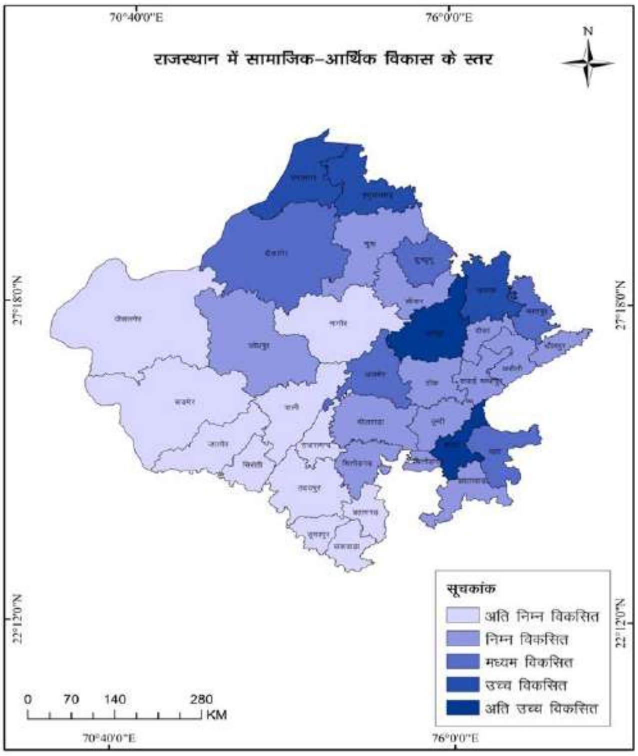

स्त्रोतः Arc GIS 10.3 की मदद से शोधार्थी द्वारा निर्मित

मानचित्र 2: राजस्थान के सामाजिक आर्थिक विकास में क्षेत्रीय विषमताएँ

मध्यम विकसित

इस विकास कटिबंध में राजस्थान के पांच जिले (अजमेर, बांरा, भरतपुर, बीकानेर व झुंझुनू) शामिल है। मध्यम विकसित क्षेत्र के समग्र सूचकांक का मान +0.16 से +0.58 के मध्य है। अजमेर व झुंझुनू जिलों में शिक्षा का उच्च स्तर व नगरीय जनसंख्या का तुलनात्मक अधिक प्रतिशत व कृषि विकास तथा प्रति व्यक्ति आय का मध्यम स्तर होने के कारण इनका समग्र विकास मध्यम स्तर दर्शाता है। बीकानेर, भरतपुर व बांरा जिलों में कृषि विकास का उच्च स्तर व शैक्षणिक विकास का स्तर, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत व प्रति व्यक्ति आय का औसत स्तर होने के कारण समग्र विकास मूल्य मध्यम प्राप्त हुआ है। राज्य में मध्यम रूप से विकसित क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का 16.47 प्रतिशत है एवं कुल जनंसख्या का 15.84 प्रतिशत भाग इसमें शामिल है।

निम्न विकसित

समग्र सूचकांक का मान –0.26 से +0.16 के मध्य मान वाले जिलों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है जिनकी संख्या 12 (भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौडगढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, सीकर व टोंक)है। इस श्रेणी के अधिकतम जिले भौतिक बांधाओं से प्रभावित है जिनमें जोधपुर, चुरू, सीकर जिले मरूस्थलीकरण से प्रभावित है एवं बाकी के जिले अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी व पठारी भूमि से प्रभावित है जो इस क्षेत्र में कृषि विकास के साथ–साथ जनसांख्यिकीय विकास पर भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। राज्य की कुल जनसंख्या का 31.98 प्रतिशत भाग व कुल क्षेत्रफल का 28. 77 प्रतिशत भाग इस श्रेणी में आता है।

अति निम्न विकसित

समग्र सूचकांक का मान –0.26 से कम मान वाले जिले इस श्रेणी में शामिल है जिनकी संख्या 11 (बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर) है। जैसलमेर, बाड़मेर व नागौर जिले के कुछ भाग में रेतीला मरूस्थल फैला होने के कारण कृषि विकास के अभाव, साथ–साथ परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर जिलों में पर्वतीय विस्तार के कारण कृषि क्षेत्र का निम्न विकास व शहरी आबादी के साथ–साथ साक्षरता दर भी निम्न है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 41.49 प्रतिशत भाग व कुल जनसंख्या का 28.83 प्रतिशत भाग इस श्रेणी में शामिल है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राजस्थान में विकास का सामान्य स्तर खराब है। कुल 33 जिलों में से 66 प्रतिशत से अधिक जिले निम्न विकसित व अति निम्न विकसित क्षेत्र में आते है। केवल दो जिले कोटा व जयपुर तुलनात्मक रूप से अत्यधिक विकसित है एवं 8 जिले मध्यम रूप से विकसित है। इसलिए यह स्थिति पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष ध्यान देने एवं नियोजन रणनीति बनाने की ओर ध्यान आकर्षित करती है।

निष्कर्ष

राजस्थान राज्य में सामाजिक–आर्थिक विकास भौतिक कारकों से प्रभावित है। पश्चिमी राजस्थान में मरूस्थलीय दशाएँ एवं दक्षिणी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की अवस्थिति के कारण इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल का 69.96 प्रतिशत भाग व कुल जनसंख्या का 60.81 प्रतिशत भाग निम्न व अतिनिम्न विकसित है। राज्य में सामाजिक–आर्थिक विकास का स्तर कृषि विकास से सकारात्मक रूप से संबंधित है। यह शोध विकास के आयामों और पिछड़ेपन की स्थिति विश्लेषण करने में मदद करता है और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए भविष्य की योजना और सूक्ष्म स्तर पर विकास के स्तर में स्थानिक भिन्नता को कम करने के लिए एक प्रासंगिक रणनीति तैयार करने के लिए भी उपयोगी है।

संदर्भ

1. किशोर, एन. (1990) : ग्रामीण राजस्थान में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन के भौगोलिक आधार, पी.एच.डी. थीसिस, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. कुमावत, वी. (2006) : टोंक जिले में सामाजिक–आर्थिक ग्रामीण विकास एवं भौगोलिक विकास, पी.एच.डी. थीसिस, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. लाजपतराय, बी. (2006): राजस्थान का भूगोल, कुलदीप प्रकाशन, जयपुर।
4. सिद्धार्थ, एम. (2009) : शेखावाटी के अधिवास प्रारूप पर आर्थिक विकास का प्रभाव, पी.एच.डी. थीसिस, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. Agricultural Statistics: Directorate of Economics & Statistics, Department of Planning Rajasthan, Jaipur. 2015-16.
6. Bagchi KK. Regional Disparities in India & Socio-Economic Development, New Century Publication, New Delhi. 2011.
7. Census Handbook. Directorate of Census Operation's, Rajasthan, Jaipur. 2011.
8. Mishra RN, Sharma PK. Rural Growth Centers for Micro-level Planning Ritu Publication, Jaipur. 2007.

9. Myrdal G. Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, Allen Lane the Penguin Press, London. 1968.
10. Olhan R. (2012): Pattern of Regional Disparities In Socio-economic Development In India: District level Analysis, SOC Indic Res. 2013;114:841-873.
11. Panday M, Patil A. Socio-Economy Regional Disparities in National Development, IRJET, 2022, 09.
12. Sharma PK. Regional Disparities in Socio-economic Development in thar Desert, IJRG, 2016, P 1-10.
13. Statistical Handbook, (2011) Directorate of Economic and Statistics Govt. of Rajasthan, Jaipur.
14. Sultana C, Aktar N. Regional Imbalances in the level of Socio-economic Department: A case Study of Malda District West Bangal, NEHU Journal. 2016;XIV:PP.69-86.
15. www.Indiastatpublication.com.
16. www.Indiastatdistricts.com.